बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 54

गलत राह

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे 230 प्रत्याशियों (कुल प्रत्याशियों का 14 फीसदी) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं।

14 प्रत्याशियों ने जानकारी दी है कि उनके खिलाफ अदालती दोषसिद्धि के आदेश हैं और मामला लंबित है जबकि 26 का कहना है कि उनके खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले हैं। इन परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से सांसद पद का प्रत्याशी बनाया है। साफ जाहिर है कि पार्टी सामान्य समझ तक को नकारने पर आमादा है। इससे पार्टी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है।

साध्वी को सजा नहीं हुई है और वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जमानत पर हैं। कानून उन्हें प्रत्याशी बनने से नहीं रोकता लेकिन उनके खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए हैं। भाजपा का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद जैसी बातों के चलते मैदान में उतारा गया है। परंतु पार्टी यह भूल गई कि मध्य प्रदेश में उसकी ही सरकार ने साध्वी को हत्या के मामले में दो बार गिरफ्तार किया। वह कहती हैं कि उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया लेकिन हिरासती अत्याचार के मामले में केवल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा इस मसले पर खामोश है।

पार्टी प्रत्याशी के रूप में उनका नामांकन भाजपा के हालिया कट्टरपंथी चयन की एक कड़ी भर है। पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जो हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे हैं। अन्य दलों ने भी अतीत में ऐसे चयन किए हैं जिनका बचाव करना मुश्किल है। मनमोहन सिंह ने 2006 में शिबू सोरेन को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाने का अप्रत्याशित निर्णय लिया था जबकि वह हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुए थे। उस वक्त विपक्ष में भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि संप्रग के कार्यकाल में केवल राजनीति ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का भी अपराधीकरण कर दिया गया है। उस लिहाज से देखें तो अब भाजपा लोकसभा का अपराधीकरण करना चाह रही है। साध्वी को यह कहते बताया गया है कि आतंकवादियों और कांग्रेस नेताओं को खत्म कर राख में बदल दिया जाएगा। क्या देश संसद में ऐसी बातें सुनना चाहता है?

कहा जाता है कि विफलता से ज्यादा सफलता किसी व्यक्ति के बारे में बताती है? विपक्ष में रहते हुए भाजपा कानून-व्यवस्था की बात करती थी लेकिन अब वह ऐसे समूहों और लोगों के साथ खड़ी है जो मुस्लिमों पर हमले करते हैं। उसके नेता जो एक वक्त अपनी संयमित भाषा के लिए जाने जाते थे, अब वे मतदाताओं को धमकाते और विभाजनकारी बातें करते पाए जाते हैं। वह 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' के खिलाफ जिस 'वास्तविक' धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, वह उसके ही कदमों से उजागर हो जाती है और हमें हिंदू राष्ट्र जैसी बातें सुनने को मिलती हैं।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

विपक्ष में रहते हुए पार्टी स्वायत्त निकायों, संवैधानिक पदों पर कांग्रेस समर्थकों की नियुक्ति और सरकार के जांच अधिकारों के दुरुपयोग की उचित आलोचना करती थी। परंतु अब वही काम भाजपा कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी ने प्रसार भारती को स्वतंत्र प्रसारण निकाय के रूप में देखा था लेकिन वह सरकार का भोंपू बन चुका है। कर तथा तमाम अन्य छापे भी एकतरफा हैं।

भाजपा इकलौता ऐसा दल नहीं है जो सार्वजनिक बहस को भद्दा बना रहा हो। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को 'चोर' कहते हैं जो स्पष्ट रूप से असंसदीय है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को 'डरपोक' कहा जो अपने आप में हास्यास्पद और बचकानी बात है। अन्य विपक्षी नेता भी कतई अलग नहीं हैं: मायावती, आजम खान और अन्य नेताओं ने भी संयम की लकीर पार की है। परंतु भाजपा वह दल है जिसने इन चुनावों को दुर्भाग्यपूर्ण स्वर दिया है।

देश की राजनीति में एक नए दल के रूप में उसे राजनीतिक आचरण और बहस में सुधार करना चाहिए था लेकिन इसके बजाय उसने प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बना दिया। हिंदुत्व को लेकर कोई कुछ भी विचार रखता हो लेकिन पार्टी के शब्द और उसके कर्म यही बताते हैं कि पार्टी उस राह पर तो नहीं चल रही है।

विनय सिन्हा

चुनाव घोषणापत्र और बुनियादी क्षेत्र

प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में हालांकि कुछ दिशाएं तय की गई हैं लेकिन इसके लिए धन कहां से आएगा, इस अहम मसले पर ध्यान नहीं दिया गया है। इनका जायजा ले रहे हैं विनायक चटर्जी

देश में बनने वाली नई सरकार से हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में आखिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? पार्टियों के चुनाव घोषणापत्रों को पढ़कर इस बारे में कोई ठोस समझ विकसित नहीं की जा सकती है। इनमें पार्टियां बड़े-बड़े वादे करती हैं और आम आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। बावजूद यह देखना सुखद है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ने इस क्षेत्र को अहमियत देते हुए अपने-अपने घोषणापत्र में स्थान दिया है। दोनों दलों में केवल भाजपा ऐसा एक दल है जिसने निवेश के आंकड़े देते हुए कहा है कि वह 2024 तक इस क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। पार्टी ने अगले पांच वर्ष में 60,000 किमी अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का वादा किया है। रेलवे में उसने वादा किया है कि पटरियों को पूरी तरह ब्रॉड गेज में बदला जाएगा और मौजूदा रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जाएगा। सन 2022 तक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा करने की बात भी कही गई। पार्टी ने 2022 तक हरेक ग्राम सभा को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही है।

भाजपा ने अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की बात कही है जिसमें सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से गैस और पानी की आपूर्ति, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी करना और राष्ट्रीय राजमार्गों को सुविधा संपन्न बनाना शामिल है। पार्टी ने नैशनल अर्बन मोबिलिटी मिशन का वादा किया है ताकि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए तकनीक की मदद से सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ाने और उनके निर्माण की गति तेज करने का वादा किया है। पार्टी ने रेलवे के पुराने पड़ चुके बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की बात भी कही है। पार्टी ने खुलकर कहा है कि वह स्वच्छ ऊर्जा को लेकर नीति तैयार करेगी और कुल ऊर्जा आपूर्ति में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी में इजाफा करेगी। कांग्रेस ने ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश बढ़ाने का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि इनके स्वामित्व और राजस्व में स्थानीय निकायों का ध्यान रखा जाएगा। पार्टी का कहना है कि लंबी अवधि में उसका इरादा घरों में एलपीजी के स्थान पर बिजली और सौर ऊर्जा की आपूर्ति उपलब्ध कराने का है। संयोग की बात है कि भाजपा ने भी सन 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को मौजूदा स्तर से दोगुना करने की बात कही है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने अपने घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे को लेकर एक अलग खंड ही समर्पित किया है। भाजपा और कांग्रेस से इतर माकपा के घोषणापत्र में उम्मीद के मुताबिक ही बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका समाप्त करने और निजी-सार्वजनिक साझेदारी की व्यवस्था खत्म करने की बात स्पष्ट रूप से शामिल है। पार्टी का कहना है कि इसके बजाय वह बिजली, संचार, रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डा क्षेत्र में अतिरिक्त आवंटन के साथ बुनियादी क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय बढ़ाने पर जोर देगी।

माकपा ने वादा किया है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी कानूनों पर लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कहा है कि जनहित की परिभाषा को और अधिक कड़ा बनाया जाएगा। भाजपा ने जहां भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई बात नहीं की है वहीं कांग्रेस ने इसका जिक्र तो किया है लेकिन वह इसके ब्योरे में नहीं गई है। उसने केवल यह वादा किया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम की विसंगतियों को दूर किया जाएगा और क्रियान्वयन के स्तर पर इन दोनों अधिनियमों की मूल भावना को बहाल किया जाएगा।

तृणमूल कांग्रेस ने भी यह वादा किया है कि वह भूमि अधिग्रहण नीति पर नए सिरे से विचार करेगी। पार्टी ने वादा किया है कि सरकार भूमि बैंक का निर्माण करेगी। इस बैंक में केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों की जमीन शामिल होगी। वादा यह भी है कि ऐसी जमीन का इस्तेमाल औद्योगिकीकरण और लॉजिस्टिक्स हब के विकास के लिए किया जाएगा। पार्टी ने स्वच्छ ऊर्जा नीति लाने का वादा भी किया है।

इन तमाम राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों का प्रमुख संदेश क्या है?

पहला, इस बार कोई नया विचार सामने नहीं आया है। केवल भाजपा ने नल से जल कार्यक्रम की सहायता से 2024 तक देश के हर परिवार को पाइप लाइन से पानी उपलब्ध कराने की बात कही है।

दूसरा, प्रमुख राष्ट्रीय दलों के वादों की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा, आम परिवारों के उपयोग से जुड़ी चीजें, सूचना एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश, गांवों के विद्युतीकरण और सड़क निर्माण के बारे में जो कुछ कहा है, उसका अनुमान लगाना बेहद आसान है। परंतु बुनियादी ढांचा क्षेत्र को लेकर किसी भी दल की समझ साफ सामने नहीं आ रही। मामला चाहे अधूरी परियोजनाओं का हो, नियामकीय गतिरोध का, नकदी संकट का, बिजली क्षेत्र की चिंताओं का या फिर स्वीकृतियों में हो रही देरी का।

परियोजनाओं को फंडिंग के लिए धन जुटाना और उसे उपलब्ध कराना एक बड़ा मसला है। यह एक गंभीर चुनौती है। सार्वभौमिक आय योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि के वादों ने पहले ही काफी दबाव उत्पन्न कर दिया है। माना यह भी जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के संकट को कम करने और सामाजिक योजनाओं (खासकर स्वास्थ्य) आदि की फंडिंग के लिए भी भारी भरकम खर्च किया जाएगा। ऐसे में बुनियादी क्षेत्र पर व्यय के लिए बहुत कम धन रह जाएगा।

भाजपा ने 5 वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है। यानी हर वर्ष बुनियादी क्षेत्र पर 20 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार अपने दम पर और तमाम विकास संबंधी फंड के जरिये भी इतना खर्च नहीं कर सकती। यह दूर की कौड़ी है।

चाहे जो भी सरकार सत्ता में आए, देश के विकास के लिए निजी निवेश को तत्काल बढ़ावा देने के अलावा कोई उपाय किसी के पास नहीं है। यह काम निजी-सार्वजनिक निवेश के जरिये किया जाना चाहिए। वाम दलों को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं है जबकि अन्य दलों के पास इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

नई सरकार के समक्ष पहली चुनौती होगी धन की कमी। इतनी भारी भरकम रकम जुटाना इतना आसान नहीं है। सरकार को निजी-सार्वजनिक निवेश, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, आदि मॉडल पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा उसे परिसंपत्ति पुनर्चक्रण, उनको बेचकर धन जुटाने जैसी बातों पर भी ध्यान देना होगा। परंतु संभवत: ये मुद्दे आम जनता को लुभाने के लिए बने घोषणापत्र के दायरे से बाहर हैं।

(लेखक फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं।)

नरेश गोयल के सपनों की उड़ान का एक अवसान

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

नरेश गोयल (उनके मित्र उन्हें एन जी कहकर पुकारते हैं) पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले हैं। जिस वक्त उनके पिता का निधन हुआ, वह बहुत छोटे थे। उनकी मां (वह उन्हें बीजी कहते) सेठ चरण दास की गोद ली हुई बहन थीं। दास पटियाला के महाराजा के प्रबंधक थे। गोयल की मां ने दास से विनती की कि वे चार भाइयों में सबसे छोटे एनजी को अपनी शरण में लें। सेठ चरण दास दूरदर्शी उद्यमी थे। सन 1965 में बहुत ही कम लोग विदेश यात्रा के लिए विमानों का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त सेठ चरण दास ने मिडल ईस्टर्न एयरवेज का जनरल सेल्स एजेंट (जीएसए) बनने की पेशकश की।

जीएसए की अवधारणा भारत में विकसित हुई। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस और केएलएम जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े-बड़े कार्यालय थे लेकिन उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो पंजाब जैसे राज्यों के दूरदराज गांवों से आने वाले लोगों की हवाई यात्रा में मदद कर सके।

जीएसए कमीशन लेकर बड़ी विमानन सेवाओं की वितरण संबंधी जरूरतें पूरी करते थे। जीएसए को एक क्षेत्र विशेष आवंटित किया जाता और दिल्ली में कार्यालय उपलब्ध कराया जाता। उन दिनों जालंधर पंजाब का केंद्र था और केएलएम और ब्रिटिश एयरवेज के जीएसए वहीं से काम करते थे।

सेठ चरण दास दूरदर्शी व्यक्ति थे। मिडल ईस्टर्न एयरवेज के अलावा वह एयर फ्रांस और दो अन्य यूरोपीय विमान कंपनियों के जीएसए बन गए। इस वक्त तक एनजी उनके पास आ गए। सेठ चरण दास ने कारोबार स्थापित कर लिया था लेकिन उन्हें इसे चलाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, एन जी ने यह कमी दूर कर दी।

एनजी ने काम के दौरान ही सबक लिए। सन 1970 के दशक के मध्य में उनकी मित्रता एयर फ्रांस के प्रबंधक से हो गई और वह गोवा के लिए कंपनी के जीएसए बन गए। परंतु वह केवल तत्कालीन बांबे में ही टिकट बेच सकते थे। यह बहुत बड़ा कारोबार था और इसने उनकी कंपनी के विकास में मदद की। बाद में यूरोप का इलाका तथा अन्य विमानन कंपनियां उनके कारोबार का हिस्सा बनीं। सन 1972 में वह गल्फ एयर के अखिल भारतीय जीएसए बन गए।

खाड़ी देशों में रोजगार की उछाल आने को थी। इसका भरपूर फायदा एनजी को मिला। सन 1970 के दशक के आरंभ में उन्होंने फिलीपीन एयरलाइंस से बात की और वह उसके क्षेत्रीय प्रमुख बन गए। हालांकि उस वक्त कंपनी भारत में एक भी उड़ान का परिचालन नहीं कर रही थी। इससे उन्हें आईएटीए में प्रवेश मिल गया। इससे उन्हें नेटवर्किंग में फायदा मिला। उन्होंने आईएटीए की हर सालाना बैठक में भाग लिया है। ऐसी ही एक बैठक में उन्होंने अमेरिकी संघीय विमानन प्राधिकार के प्रमुख मैरियन ब्लैक्ले से कहा था कि वह इंतजार करें उन्हें उनसे बात करनी है। इसके बाद एनजी कक्ष में मौजूद तमाम लोगों से हाथ मिलाते और चर्चा करते रहे और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रतिनिधि प्रतीक्षा करता रहा।

सन 1996 में सीएम इब्राहिम गठबंधन सरकार में विमानन मंत्री थे। नरेश गोयल के लिए यह समय मुफीद था। उस वक्त घरेलू विमानन कंपनी में 49 फीसदी एफडीआई की नीति थी। वहीं अनिवासी भारतीयों के लिए यह 100 फीसदी थी। उस वक्त तक वह अनिवासी भारतीय बन चुके थे। हालांकि कोई विदेशी विमानन कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निवेश नहीं कर सकती थी। इस प्रकार उन्होंने एक नई विमानन कंपनी में सिंगापुर इंटरनैशनल एयरलाइंस के निवेश को रोका, जिसे टाटा समूह शुरू करना चाहता था। सरकार में उनकी पहचान ने उनकी मदद की।

जेट में चुनिंदा राजनेताओं की श्रेणी को उन्नत करने के स्पष्ट निर्देश थे। इसके अलावा भी उनको प्रभावित करने के और तरीके थे। एक बार शरद पवार एक हवाई अड्डे के लाउंज में बैठकर क्रिकेट देख रहे थे। नरेश गोयल ने अपने जीवन में भी क्रिकेट नहीं खेला था न ही उन्हें उसके बारे में कुछ पता था। इसके बावजूद वह पवार के बगल में बैठकर खेल पर ऐसे निगाह जमाए रहे जैसे उन्हें इस खेल में बहुत दिलचस्पी हो। जब-जब पवार ताली बजाते, वह भी ताली बजाते। उनको जानने वाले यह दिलचस्प नजारा देखकर हंस रहे थे। सन 2008 में जेट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली थी। हैदराबाद में एयरशो हो रहा था। उस वक्त फलकनुमा पैलेस होटल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। प्रफुल्ल पटेल नागर विमानन मंत्री थे और चर्चा थी कि जेट को अमेरिका में उड़ान संचालित करने की इजाजत मिल सकती है। यह बड़ा सौदा था।

उसी वक्त कंपनी का आकार कम करने की कोशिश में एनजी ने केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ में कई लोगों की छंटनी कर दी। तो एक ओर जहां फलकनुमा में शानदार पार्टी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद एयरपोर्ट पर जेट के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को संदेश भेज रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों का पेट भरना है। तब सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कहा था कि वह अपने कर्मचारियों को वैसे कभी नहीं निकालेगी जैसे निजी विमानन कंपनियां निकालती हैं।

फलकनुमा में मौजूद पटेल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वह बेहद नाराज हुए। एनजी एक योजना लेकर आए। उन्होंने उसी शाम गंभीर मुखमुद्रा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा, 'बीती रात मेरी मां सपने में आई। उन्होंने कहा कि नरेश तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों के परिवार और बाल बच्चे हैं। तुम उनको ऐसे कैसे निकाल सकते हो। इसलिए मैं अपने सारे ओदश वापस लेता हूं, किसी को काम से नहीं निकाला जाएगा।' जाहिर है बाद में इन कर्मचारियों को ऐसी दूरदराज जगहों पर स्थानांतरित किया गया कि उनके पास काम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था।

विडंबना देखिए कि नरेश गोयल को उड़ान से नफरत है। वह हर बार उड़ान के समय घबरा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब जेट एयरवेज भी शायद ही उड़ान भरे।

कानाफूसी

सुंदर पिचाई का वोट!

पिछले दिनों एक मीडिया हाउस उस समय दिक्कत में पड़ गया जब उसने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की एक तस्वीर के साथ लिख दिया कि उन्होंने चुनाव में अपना वोट दिया। इस तस्वीर में पिचाई कई लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोगों ने इस खबर को रीट्वीट किया। पिचाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वहां के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि कैसे हाल ही में रिलीज एक फिल्म में अभिनेता विजय ने सुंदर रामासामी नामक ऐसा किरदार निभाया है जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ है और अपना वोट देने अपने वतन वापस आता है। फिल्म में रामासामी के किरदार को जब यह पता चलता है कि किसी ने उसका वोट डाल दिया है तो वह न केवल नए चुनाव करवाता है बल्कि अपने दम पर सरकार भी बनवाता है। परंतु असल बात कुछ और निकली। पिचाई की यह तस्वीर 2017 की थी जब वह आईआईटी खड़गपुर गए थे, जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। दूसरी बात यह कि अमेरिकी नागरिक होने के नाते पिचाई वैसे भी भारत में होने वाले चुनाव में वोट नहीं डाल सकते।

आपका पक्ष

किसानों के लिए छलावा न्याय योजना

आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां किसानों के लिए लगातार घोषणाएं करना मुनासिब समझ रही हैं। अबतक के सभी आम चुनावों में घोषणापत्रों में किसानों के हितों से जुड़े आर्थिक मुद्दों को अहमियत मिलती आ रही है। साथ ही गरीबी हटाओ, रोजगार गारंटी जैसे अनेक आर्थिक मुद्दों ने नतीजों को काफी प्रभावित किया है। लेकिन सभी मुद्दे केवल राजनीतिक वादों तक ही सीमित रहते हैं। किसानों की कर्ज माफी तथा न्यूनतम आय की गारंटी से किसानों की दशा में बदलाव नहीं दिखता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी यह घोषणा की कि सत्ता में आते ही गरीबों को सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। घोषणा तो गरीबों के हित में है लेकिन ऐसा करने से राजकोषीय घाटा होना निश्चित है। सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कई योजनाएं बनाई हैं जो किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही हैं। लेकिन सही मायने में उन योजनाओं से किसानों की समस्या का निदान संभव नहीं लगता। अत: किसानों के लिए सरकार को एक विशेष कदम उठाने की जरूरत है। देश में किसानों को व्यापारी क्यों नहीं माना जाता है? होना यह चाहिए कि किसान स्वयं ही श्रम और धन लगाकर अपनी उपज का मूल्य निर्धारण खुद करे। साथ ही किसानों को भी वही लाभ अर्जित करना चाहिए जो एक व्यापारी अर्जित करता है। सरकार कोल्ड स्टोरेज में 2 फीसदी निवेश करती है जो न के बराबर है। किसानों की समस्या दूर करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लाभकारी है लेकिन इससे समस्या का जड़ से खत्म होना संभव नहीं लगता है। अत: किसानों को सदैव के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना विफल प्रतीत हो रही है। इसके लिए किसानों को व्यापारिक दायरे में लाना और व्यापारियों की भांति उनको अधिकार प्रदान करना जरूरी है जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

लालजी जायसवाल, प्रयागराज

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को 115 सीटों के लिए होगा

जेट का डूबना और प्रतिस्पर्धी का चढ़ना

जेट एयरवेट के घाटे में चलने तथा ऋण का भार बढ़ने की वजह से इसका परिचालन गुरुवार से बंद हो गया है। जेट के बंद होने से उसके हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई। इन कर्मचारियों को पिछले दो-तीन महीने से वेतन भी नहीं मिला था। गुरुवार को जेट के कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया तथा अपनी आजीविका छिन जाने का गम दिखाया। दूसरी ओर अन्य विमानन कंपनियों को इसके बंद होने से फायदा मिला है। दूसरी कंपनियों ने अपने किराये में बढ़ोतरी कर दी। वहीं अब वे जेट के पारिचालन मार्ग और विमान हैंगर लेने की कवायद भी कर रही हैं। इन विमानन कंपनियों का एक प्रतिस्पर्धी स्वत: समाप्त हो गया।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।